www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 332 | जौनपुर, गुरूवार, 23 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए जम्मू–कश्मीर, आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों पर अपना स्पष्ट रुख दोहराया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय अपने आंतरिक हालात और जनता के हितों पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ष्आकृतिक संसाधनरू शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींवष विषय पर आयोजित बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। भारत की ओर से कहा गया कि जम्मू–कश्मीर का भारत के साथ संबंध संवैधानिक और कानूनी रूप से पूरी तरह स्पष्ट है। राजदूत हरीश ने कहा कि पाकिस्तान बार–बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर तथ्यहीन प्रचार करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जम्मू–कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू–कश्मीर से जुड़ा वास्तविक मुद्दा केवल इतना है कि पाकिस्तान अब भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किए हुए है और उसे इस पर ध्यान देना चाहिए।भारत ने अपने संबोधन में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।

छात्रों की मांग जायज सरकार जवाबदेही से भाग रही है : प्रियंका चतुर्वेदी

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) की दिग्गज नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री ध र्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में लगातार हुई कथित गड़बड़ियों और छात्रों के आंदोलन को संभालने में सरकार विफल रही है। सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है और लोकतांत्रिक विरोध–प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास कर रही है।प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को लंबे–लंबे एक्स पोस्ट लिखने के बजाय अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों की मांग पूरी तरह स्पष्ट है और वे किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। छात्र न तो राजनीति कर रहे हैं और न ही कोई अनुचित मांग रख रहे हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री अपने सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे आए हजारों लोगों के कमेंट पढ़ लें, तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि देश का जनमत क्या है। सरकार अपनी विफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी स्वयं सरकार की है।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, पेपर लीक मामलों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन- पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पेपर लीक के सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर पोस्ट किया, ष्देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट में आगे लिखा, इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने फैसले को छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने श्एक्सश पोस्ट में लिखा, ष्विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो। रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी वजह से नीट की दोबारा परीक्षा जल्द कराई गई और उसका परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किया गया, ताकि छात्रों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।

राजस्थान सरकार ने एनएफएसए का दायरा बढ़ाया, स्वैच्छिक त्याग से जरूरतमंदों तक पहुंची खाद्य सुरक्षा

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान सरकार ने श्नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्टश (एनएफएसए) के तहत फूड सिक्योरिटी कवरेज का दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक कर दिया है। अधिकारियों ने इस कामयाबी का श्रेय राज्य के श्गिव अपश अभियान को दिया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना राशन का अधिकार छोड़ दिया था। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लगभग 93.5 लाख आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से एनएफएसए लाभ छोड़ने के बाद, 1,00,56,511 नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। गोदारा ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से सरकार उन जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचा पाई है जो पहले इस योजना से बाहर थे। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राजस्थान में लाभार्थियों की संख्या की एक निश्चित सीमा (लगभग 4.46 करोड़) तय है। चूंकि कोटा पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए कई पात्र परिवार इन लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए, राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2024 को श्गिव अपश अभियान शुरू किया, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपने खाद्य सुरक्षा लाभ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगभग तीन महीने बाद, 26 जनवरी, 2025 को एनएफएसए पोर्टल को फिर से खोला गया, जिससे पात्र परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने का मौका मिला।

तमिलनाडु के सीएम ने राहुल गांधी की हिरासत की निंदा की, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग दोहराई

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को नीट विवाद को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को श्अलोकतांत्रिकश बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर विजय ने कहा कि श्संसद चलोश मार्च में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही विपक्षी पार्टियों के साथ टीवीके मजबूती से खड़ी है। उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रति पार्टी के अडिग विरोध को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की स्थापना के बाद से ही टीवीके लगातार यह कहती रही है कि नीट को स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का फायदा नहीं उठाएगी और कहा कि इस परीक्षा ने छात्रों और उनके परिवारों को भारी कठिनाई में डाल दिया है। संरचनात्मक सुधारों की मांग करते हुए विजय ने कहा कि स्थायी समाधान शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करना है, जिससे राज्यों को अपनी प्रवेश नीतियां निर्धारित करने का अधिकार मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक ये संवैधानिक परिवर्तन नहीं हो जाते, तब तक केंद्र सरकार एक विशेष समवर्ती सूची बनाए।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु कैंपेन शुरू किया

अहमदाबाद, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद से ड्रॉपआउट बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे अभियान समरस विद्या सेतु की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा देने वाली लीडरशिप में ड्रॉपआउट रेट घटकर दो प्रतिशत रह गया है। अब इसे जीरो ड्रॉपआउट बनाने के मकसद से राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ चुके 80 हजार से ज्यादा बच्चों को ढूंढकर उन्हें शिक्षा की मेनस्ट्रीम में वापस लाने का प्लान बनाया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इसके लिए राज्य स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जिलेवार लिस्ट तैयार की गई है। टीचर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक नेता मिलकर माता–पिता से संपर्क करेंगे। हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से सही स्टैंडर्ड (1 से 12) में एडमिशन दिया जाएगा और जो बच्चे पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, उनके लिए खास देखभाल और सप्लीमेंट्री एजुकेशन का भी इंतजाम किया गया है। टीचर और माता–पिता के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुजरात पूरे देश में बिजनेस और रोजगार के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिशन के इस दौर में राज्य के युवाओं को रोजगार का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए हायर एजुकेशन जरूरी है। माता–पिता को भी जागरूक होना होगा और यह पक्का करना होगा कि उनके बच्चे रेगुलर स्कूल जाएं। यह कामयाबी सिर्फ सरकारी कोशिशों से नहीं, बल्कि सभी की कोशिशों से मुमकिन होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, जिसमें काम करने का मौका मिलने पर आत्म–संतुष्टि महसूस होती है। उन्होंने कहा कि आज टीचर स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर बहुत सेंसिटिव और कमिटेड हो गए हैं। आज अगर कोई बच्चा दो दिन स्कूल नहीं आता है, तो टीचर उसके घर पहुंचकर वजह पता करते हैं। पटेल ने गर्व से कहा कि आज जैसे–जैसे सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाई का लेवल सुधर रहा है, वैसे–वैसे कई स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं।

युवाओं के भविष्य और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया - राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मांगें स्पष्ट हैं और सरकार को उन पर सीधा जवाब देना चाहिए। एक्जिक्यूटिव ब्रांच राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ–साथ उसकी खामियों को बढ़ावा दिया गया और कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी ने लिखा कि युवाओं के भविष्य के साथ हुए नुकसान की जिम्मेदारी सरकार से अलग नहीं की जा सकती और केवल नई घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। छात्रों की तीन प्रमुख मांगों का किया उल्लेख राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रदर्शनकारी छात्रों की तीन प्रमुख मांगों का भी जिक्र किया।

उनके अनुसार छात्रों की मांगें इस प्रकार हैंकृ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित हिंसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। पीएम मोदी ने किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगी।

असम में बाढ़ : मुख्यमंत्री सरमा ने नुकसान को अभूतपूर्व और अनुमान से अधिक बताय

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को ऊपरी असम के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ से प्रभावित सोनारी उपमंडल का दौरा किया और जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने जलमग्न गांवों का दौरा किया, राहत शिविरों में शरण लिए परिवारों से मुलाकात की और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर जिला अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में फंसे निवासियों तक पहुंचने में बचाव एजेंसियों के सामने आ रही रसद संबंधी चुनौतियों की भी समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने मौजूदा बाढ़ को श्अभूतपूर्वश आपदा बताया और कहा कि तबाही का पैमाना शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, हालात अभूतपूर्व हैं। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है, जबकि कई अन्य अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। हमने कई मौतें देखी हैं और राहत कार्य अभी भी जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), भारतीय सेना, असम पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मी फंसे हुए लोगों को बचाने और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सरमा ने कहा कि राज्य को बाढ़ राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है।

नीट मामले में नितिन नवीन की विपक्ष को खुली चुनौती, सदन में करें चर्चा, सरकार हर सवाल का देगी जवाब

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार नीट समेत युवाओं से जुड़े सभी विषयों पर सदन में चर्चा करने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस चर्चा से बच रहा है। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारी सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े हर मुद्दे पर हर स्तर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वे सदन के पटल पर चर्चा के लिए आएंगे तो उनका दोहरा चरित्र जनता और युवाओं के सामने उजागर हो जाएगा।" नितिन नबीन ने कहा, "हम खुली चुनौती देते हैं कि आइए, संसद के पटल पर छात्रों और युवाओं से जुड़े हर विषय, नीट के मुद्दे और अन्य सभी मामलों पर चर्चा करें। भाजपा के सांसद हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं और एनडीए सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।" उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का 50–60 वर्षों का इतिहास युवाओं को गुमराह करने और उनके मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार ने युवाओं के भविष्य को सही दिशा देने का काम किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में शिक्षा संस्थान, कोचिंग संस्थान और अन्य सुविधाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

अयोध्या से चित्रकूट होते हुए बांदा के लिए प्रतिदिन बस सेवा शुरू

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। गुरुवार से अयोध्या बस स्टेशन सिविल लाइन से प्रयागराज,चित्रकूट और बांदा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की प्रतिदिन बस सेवा शुरु हुई। इस नई बस सेवा से भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम से राम जी की तपोभूमि चित्रकूट के बीच आवागमन पहले की अपेक्षा और अधिक सुगम हो गई।इस संबंध में सहायक प्रबंधक रोडवेज ने बताया कि यह वातानुकूलित बस अयोध्या बस स्टैंड से प्रातः 9:45 पर चलेगी और बांदा शाम को 7:35 पर पहुंचेगी।जो रात में वहीं पर रुकेगी और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे रवाना होगी।उन्होंने बताया कि इस बस के चलने से सबसे अधिक लाभ अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। बताया कि यह बस अयोध्या बस स्टैंड से सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ प्रयागराज चित्रकूट होते हुए बांदा तक जाएगी उसके बाद दूसरे दिन सुबह 6:30 यही बस चित्रकूट प्रयागराज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या डिपो होते हुए अयोध्या धाम, गोंडा और फिर गोंडा से वापस 8:50 पर अयोध्या बस स्टैंड पर आएगी जो दूसरे दिन फिर बांदा के लिए रवाना होगी।बताया कि इस बस सेवा के शुरू होने से अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं तथा चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा और सुविधा जनक परिवहन उपलब्ध होगा।इससे समय और यात्रा की परेशानी दोनों में कमी आएगी। धार्मिक दृष्टि से अयोध्या और चित्रकूट का श्रीराम के जीवन से गहरा संबंध है।अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जबकि चित्रकूट उनके वनवास की प्रमुख स्थली रही है।ऐसे में यह बस सेवा केवल परिवहन का माध्यम नहीं,बल्कि श्रीराम से जुड़े दो प्रमुख तीर्थों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी भी साबित होगी।बताया कि इससे जहां एक और रामनगरी से चित्रकूट धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आराम मिलेगा वहीं राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी।

संपादकीय

संसद या सियासी अखाड़ा

विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का आज क्या औचित्य रह गया है? अगर ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े और संसद के बीच क्या फर्क रह जाएगा? मानसून सत्र की शुरुआत के साथ संसद का नजारा कुछ बदला नजर आएगा। यह संभवतरू पहला मौका है, जब बिना चुनाव हुए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के संख्या बल में गुणात्मक बदलाव हुआ दिखेगा। बजट सत्र के बाद तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) बड़ी टूट–फूट हो चुकी है, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इससे बिना नया जनादेश आए ही सत्ताधारी एनडीए मजबूत हो गया है। इस हद तक कि अभी दो महीने पहले लोकसभा सीटों के परिसीमन के मकसद से लाया गया जो विधेयक गिर गया था, सत्ता पक्ष उसे फिर से लाने की तैयारी में दिखा है। इसी तरह विवादास्पद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक–2025 और गिरफ्तारी होने पर 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्रीध मंत्री पद खत्म करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को भी लाने की चर्चा थी (जिसका इरादा शायद टाल दिया है)। पिछले सत्र तक इन विधेयकों के पारित होने की संभावना बेहद कमजोर थी। अभी भी इनके लिए सरकार संख्या बल का पूरा इंतजाम नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ और जोड़–तोड़ में कामयाब रही, तो इनके पारित होने की संभावना बन सकती है। मगर यही समस्या है। वह संभावना 2024 में आए जनादेश की भावना के विपरीत होगी। मुद्दा है कि दांव–पेच से जनादेश की भावना को इस तरह धता बताने का चलन आम हो जाता है, तो फिर विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का क्या औचित्य रह जाएगा? ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े में होने वाली जोर–आजमाईश और संसदीय प्रक्रियाओं के बीच क्या फर्क रहेगा? क्या उसके बाद भी संसद को बहस के जरिए अधिकतम संभव सहमति निर्माण का मंच माना जा सकेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इन प्रश्नों के उत्तर लगातार नकारात्मक होते गए हैं। संसद शोर, हंगामे, वॉकआउट, बहिष्कार, और कई बार तो शारीरिक बल के जरिए झड़पों का स्थल बनती चली गई है। नतीजतन, अधिवेशनों से पहले गंभीर बहस से ज्यादा अपेक्षा टकराव और तू तू–मैं– मैं की रहने लगी है। मानसून सत्र के पहले भी राजनीतिक क्षितिज पर यही माहौल हावी नजर आया है।

विक्रम–1: नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

ललित

भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टि और नवाचार का संगम हो तो आकाश भी सीमा नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रारंभ बन जाता है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम–1' का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान–प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते राष्ट्र का एक नया घोषणापत्र है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 'मिशन आगमन' के अंतर्गत हुई यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। निश्चित ही विक्रम–1 नए भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन है। विक्रम–1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है। आज उसी विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति स्काईरूट एयरोस्पेस के रूप में दिखाई देती है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय दुनिया में केवल कुछ ही देशों के निजी उपक्रम ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर पाए हैं। भारत अब उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जहां नवाचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नई संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेसएक्स ने जिस निजी अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत की थी, भारत ने अब उसका अपना स्वदेशी संस्करण प्रस्तुत कर दिया है। मजबूत तथा कम लागत वाला है। श्री–डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसके निर्माण खर्च को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार भारत के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा। आज दुनिया में संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए हजारों छोटे उपग्रहों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में भारत कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 'विक्रम–1' को विकसित करने वाली निजी कंपनी 'स्काईरूट एयरोस्पेस' ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण कर न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह संदेश दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। गौर कीजिए, अप्रैल 1975 में जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, तब उसका नामकरण महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। यह सफलता केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं है। यह उस नई नीति का परिणाम भी है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और स्टार्टअप के लिए खोलने का साहसिक निर्णय लिया। नई अंतरिक्ष नीति, इन–स्पेस जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार प्रावधानों ने भारतीय युवाओं के सामने नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। आज देश में अनेक स्पेस स्टार्टअप उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष संचार और डेटा सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। किन्तु हर सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। विक्रम–1 की पहली उड़ान सफल अवश्य रही है, परंतु अंतरिक्ष उद्योग में स्थायी सफलता केवल एक प्रक्षेपण से सुनिश्चित नहीं होती। स्काईरूट एयरोस्पेस को अब वैश्विक बाजार में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब तथा चीन की अनेक निजी कंपनियों जैसी सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। नियमित ग्राहक, समय पर प्रक्षेपण, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता तथा भविष्य में पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक विकसित करना उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। अंतरिक्ष उद्योग में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और वह निरंतर सफल अभियानों से ही अर्जित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बीच एक गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है–क्या इसरो अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख पाएगा? हाल के वर्षों में अनेक अनुभवी वैज्ञानिक निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। इसका कारण केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति, अनुसंधान की स्वतंत्रता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण भी है। इसरो ने भारत को चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य–एल1, गगनयान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां दी हैं। सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय परिणाम देकर इसरो ने पूरी दुनिया का सम्मान अर्जित किया है। किंतु यदि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक धीरे–धीरे संस्थान से बाहर जाते रहे तो दीर्घकाल में अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नए मिशन तैयार करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रेरित, सम्मानित और संतुष्ट बनाए रखना भी है। सरकार को चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं, निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां विकसित करे। सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का वातावरण तैयार होना चाहिए। निजी क्षेत्र इसरो का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी बन सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, उसी प्रकार भारत में इसरो और निजी कंपनियों का समन्वय देश को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि अंतरिक्ष विज्ञान को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर तक पहुंचाया जाए। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं का विषय न रहकर जन–आंदोलन बने। युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवाचारकर्ताओं को स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। यदि प्रत्येक राज्य में स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएं, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान साझेदारी विकसित की जाए तथा अंतरिक्ष तकनीक में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो भारत अगले दशक में विश्व का अग्रणी अंतरिक्ष नवाचार केंद्र बन सकता है। भविष्य की आकाशीय सफलताओं की नई जमीन तैयार करने के लिए कुछ रचनात्मक कदम अत्यंत आवश्यक हैं–इसरो और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ होंय पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक और हरित प्रणोदन (ग्रीन प्रोपल्शन) पर विशेष निवेश किया जाएय अंतरिक्ष विनिर्माण के लिए स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएय युवाओं के लिए अंतरिक्ष उद्यमिता को बढ़ावा ।

भारत में खो गई है जवाबदेही

श्रुति व्यास

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसे देखते हुए पहली बार लगा कि भारत में केवल राजनीति नहीं बदली है, जवाबदेही भी बदल गई है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव खारिज किया था। फैसला सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार करने के बजाय आपातकाल लगाया। वह लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक सच्चाई भी थी। आरोप प्रधानमंत्री पर था और पूरा देश जानता था कि जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। सत्ता बचाने का उनका तरीका लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन जवाबदेही का अंतिम पता किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। भारत का हर नागरिक जानता–समझता था चौदह वर्ष बाद यही कसौटी राजीव गांधी के सामने आई। वे मिस्टर क्लीन की छवि लेकर सत्ता में आए, लेकिन बोफोर्स विवाद उनकी पूरी राजनीतिक पहचान पर छा गया। हालांकि अदालत कभी यह साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिश्वत ली थी। फिर भी जनता ने राजनीतिक फैसला दे दिया। प्रधानमंत्री के इतने निकट हुआ सौदा प्रधानमंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी भी बना। और1989 में उसकी कीमत उन्हें सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी। फिर मनमोहन सिंह आए। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। लेकिन लोकतंत्र व्यक्ति की नहीं, पद की जवाबदेही भी तय करता है। 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन विवाद उनके कार्यकाल में सामने आए। लंबे समय तक कोयला मंत्रालय स्वयं उनके पास था। इसलिए ष्मुझे जानकारी नहीं थीष जैसी सफाई राजनीतिक रूप से टिक नहीं सकी। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपनी जेब भरी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुँच चुका था। 2014 में उसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस ने चुकाई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंहकृतीनों एक–दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी उनमें एक समानता थी। उनके आसपास पैदा हुआ बड़ा विवाद अंततरू प्रधानमंत्री तक पहुँचता था। कभी प्रतिष्ठा जाती थी, कभी सरकार, कभी दोनों। उस समय जवाबदेही को सत्ता के शिखर (प्रधानमंत्री पद) तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगता था। यही भारतीय लोकतंत्र का विकास था। उपलब्धि थी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आदत थी। लोकतंत्र में सरकार का चेहरा ही उसकी अंतिम जवाबदेही भी होता था। यहीं मुझे लगता है कि पिछले दशक में सबसे बड़ा बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का दशक विवादों से खाली नहीं रहा। किसानों का लंबा आंदोलन हुआ। देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सांसद के खिलाफ संघर्ष किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार–बार लीक हुए। भर्ती प्रक्रियाएँ संदेह के घेरे में आईं। लद्दाख में असंतोष बना। कई मौकों पर नागरिकों ने सरकार से जवाब माँगा। लेकिन इन सबमें एक बात समान रही। विवाद जंतर–मंतर, दिल्ली के प्रवेश दरवाजों तक और सरकार तक भी पहुँचे, मगर प्रधानमंत्री तक नहीं। यही इस दौर की सबसे असाधारण राजनीतिक विशेषता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध करने वाले वही वर्ग थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति के केंद्र में रखा था। अच्छे दिनों के वायदे में किसान राष्ट्र की रीढ़ बताए गए थे। युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। ष्डेमोग्राफिक डिविडेंडष केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल की राजनीतिक कथा थी। 2018 में तुमकुरु के एक युवा सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि समाज के लिए षविद्यार्थी देवो भवष मंत्र है, तो उनके लिए ष्युवा शक्ति देवो भवष मंत्र है। फिर प्रश्नपत्र लीक का दौर आया। करोड़ों युवाओं ने केवल परीक्षाएँ नहीं खोईंय उन्होंने व्यवस्था पर अपना भरोसा भी खोया। स्वाभाविक अपेक्षा थी कि जिसने युवाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया, वही उनके सबसे कठिन समय में सबसे पहले दिखाई देगा। पहले सन्नाटा रहा। फिर प्रतीक्षा। फिर वही मंत्री अपने पद पर बने रहे जिनके विभाग पर सवाल उठ रहे थे। धीरे–धीरे शिकायत से अधिक चर्चा शिकायत करने वालों पर होने लगी। भारतीय राजनीति में यह नई रणनीति नहीं है। जब किसी प्रश्न का उत्तर कठिन हो, तो बहस को प्रश्न से हटाकर विरोध पर ले जाइए। धीरे–धीरे मूल प्रश्न ही धुँधला पड़ जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की सात शीर्ष महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के बाद भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी लंबे समय तक पद पर बने रहे। राष्ट्रीय परीक्षा विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठे। हर बार राजनीतिक बहस किसी मंत्री, किसी सांसद या किसी संस्था तक पहुँची, लेकिन शायद ही कभी प्रधानमंत्री तक पहुँची। पहले ऐसा नहीं होता था। इनमें से हर विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय के इतना निकट था कि भारतीय राजनीति के पहले के दौर में वह एक–दो सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ता।

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से सुलगते सवाल और राजनीतिक निहितार्थ

विकास

कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो आह्वान केवल एक विरोध मार्च नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। खासकर जिस तरह से इस आंदोलन को छात्र आंदोलन का स्वरूप दिलवाया जा चुका है, वह डीप स्टेट के इशारे पर बनी विपक्ष की शातिर सरकार घेरो रणनीति का कमाल भी करार दिया जा रहा है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र के दौरान गत 20 जुलाई को जंतर–मंतर से संसद की ओर मार्च करने के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और कूच किया, वह बिल्कुल संगठित राजनीतिक आंदोलन के तर्ज पर हुआ। मजे की बात तो यह कि संसद के निकट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो पूर्व प्रायोजित झड़प हुई और उसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इससे यह संसद मार्च राष्ट्रीयध अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। बड़े बड़े न्यूज चौनल्स और अखबारों के दफ्तरों में इससे जुड़े कई नीतिगत सवालों पर भी बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर जहां सरकार विरोधी भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे, वहीं सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों की कारगुजारियों के वीडियो साझा कर दिए, जिससे लोगों की सहानुभूति पुलिस और सरकार के साथ बनी रही। यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी समर्थक ष्संसद चलोष मार्च के लिए जंतर–मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा–पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। चूंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गई। देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट (छम्ज्) पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखाई–सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर ब्रच् प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और मांगपत्र ग्रहण किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं। सवाल है कि संसद मार्च के क्रम में जो कुछ गड़बड़ हुआ, क्या वह लोकतांत्रिक है, सही था या गलत? तो जवाब होगा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। वहीं, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कदम है। फिर भी संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारियों की ओर से कुछ कुछ गलत हुआ जो अनुचित लगा। यदि प्रदर्शनकारियों ने निषिद्ध क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वह कानून–व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। वहीं, यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि, इस पर अलग–अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सभी तथ्यों के गोलमोल जवाब ही मिले हैं, जिनपर एतबार करना मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसका अंतिम सत्यापन अभी होना बाकी है, कई अनकही कहानियां गढ़ रहे हैं। इससे सरकार सांसत में है और विपक्ष तरह–तरह के आरोप लगाकर सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक समाधान का सर्वोत्तम रास्ता संवाद और कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान है। भले ही किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी मांगें रखना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस संसद मार्च के क्रम में देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल पर, जिस प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना या सुरक्षा बलों से टकराव की जो प्रवृति दिखाई दी, वह विपक्षी दलों का परोक्ष कुचक्र नहीं तो क्या है? आखिर इस देशद्रोही प्रवृति को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि पुलिस बल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है कि क्या स्थानीय जिलाधिकारी और डीसीपी के पास छात्र समूह को काबू में रखने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी? और यदि थी तो फिर इतना सबकुछ कैसे हुआ? वहीं कोई पुलिस कर्मी कैसे पिट गया और घायल हुआ? आखिर किसी दुकानदार को तोड़–फोड़ का सामना क्यों और कैसे करना पड़ा? जनपथ बाजार की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे। वहीं, अनियंत्रित युवा भीड़ क्यों जुटने दी गई और उनको काबू में रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त क्यों नहीं किये गए थे? कॉकरोच जनता पार्टी के ष्संसद चलोष आह्वान के राजनीतिक मायने केवल एक विरोध मार्च तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय राजनीति में युवाओं के असंतोष, डिजिटल आंदोलन और पारंपरिक दलों के प्रति अविश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। हालांकि ब्रच् स्वयं को व्यंग्यात्मक '(जपतपबंस) आंदोलन बताता है, लेकिन इसके मुद्दे गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैंरू– पहला, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दबाव की राजनीति। दूसरा, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के असंतोष को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास। तीसरा, विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर और चौथा, सरकार के लिए कानून–व्यवस्था बनाए रखते हुए ।

मानसून सत्र से पहले सत्ता का मौसम खराब

शुरु हो रहे संसद के मानसून सत्र में सियासत की गरज और चमक देखने मिलेगी, इतना तो तय था लेकिन सत्र शुरु होने से पहले सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी फूट पड़ेगी, इसका अनुमान मोदी सरकार को भी नहीं रहा होगा। पिछले चार हफ्तों से जंतर–मंतर पर धरना कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने ये ऐलान किया था कि 20 जुलाई को जंतर–मंतर से संसद मार्च किया जाएगा। इस ऐलान में विपक्ष के कई दलों की भी सहमति थी। लेकिन इस बीच शुक्रवार और शनिवार को दो बड़ी घटनाएं हुईं। एक तो देहरादून में राहुल गांधी ने 17 जुलाई शुक्रवार को छात्रों की गूंज रैली की, जिसमें कम से कम दो लाख छात्र शामिल हुए। जबकि इस रैली की जगह पहले सरकार ने बदली, फिर रास्ते के पेड़ काटे ताकि लोगों को आने में परेशानी हो और साथ ही एक लोकगायिका का कार्यक्रम रखवा दिया, जिसमें मुफ्त प्रवेश दिया गया। लेकिन इसके बावजूद युवाओं ने मनोरंजन की जगह अपने भविष्य की चिंता करते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां भाजपा को बड़ा झटका लगा। इधर शनिवार को मोदी सरकार के कहने पर जंतर–मंतर से 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन उठा कर ले जाया गया। वहां जिस दबे–छिपे तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उससे जाहिर हो गया कि सरकार आंदोलनकारियों को डराना–धमकाना चाहती है। असल में पहले मोदी सरकार ने इस प्रदर्शन को हल्के में लिया था, मुमकिन है उसे लगा हो कि थोड़े बहुत नारे लगाने और भाषण देने के बाद मंच खाली हो जाएगा। हालांकि सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस ने कभी पानी, कभी बिजली रोककर तो कभी तिरपाल लगाने में रुकावट डाल कर आंदोलनकारियों को परेशान किया, प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और विपक्ष के नेताओं का जंतर–मंतर पर आने का सिलसिला तेज हुआ तो सरकार के कान खड़े हुए। शुक्रवार को अचानक दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया। शुक्रवार सुबह दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा जब वन महोत्सव कार्यक्रम में थे, तब उन्हें अपने तबादले और नए कमिश्नर के आने की जानकारी मिली। यहां तक कि हेडक्वार्टर को भी इसकी जानकारी नहीं थी, जो काफी अजीब बात है। सुप्रीम कोर्ट के श्प्रकाश सिंह जजमेंट्य और राज्य पुलिस अधिनियमों (जैसे राजस्थान पुलिस अधिनियम, आदि) के अनुसार, एक पुलिस कमिश्नर का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल निर्धारित किया गया है। इस हिसाब से देखें तो सतीश गोलछा पिछले साल ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे, तो उन्हें अभी एक साल और इस पद पर रहना था। लेकिन उन्हें बदलने का आदेश अचानक आया। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रहे 1994 बैच के अधिकारी अनुराग कुमार ने शुक्रवार को पद संभाला और शनिवार सुबह जंतर–मंतर से सोनम वांगचुक उठा कर अस्पताल पहुंचा दिए गए।रविवार को उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर अदालत ने सुनवाई की कि उन्हें सफदरजंग की जगह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया जाए। लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्करणा की एकल बेंच ने मामले की विशेष सुनवाई करते हुए कहा कि श्हर जिंदगी कीमती है।च इससे पहले दिल्ली पुलिस का तर्क भी यही था कि सोनम वांगचुक की हालत खराब थी। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं लगता। इसी मोदी सरकार में 2018 में प्रो.जी डी अग्रवाल ने भी गंगा नदी बचाने के लिए 111 दिनों के अनशन के बाद दम तोड़ दिया था। लेकिन तब मोदी सरकार ने उन्हें बचाने की

कोई कोशिश नहीं की और न ही उनकी मांगों पर ध्यान दिया। खास बात यह है कि 2010 में भी प्रो. अग्रवाल ने 38 दिनों का अनशन किया था, तब यूपीए सरकार ने उनकी मांग भी मानी और अनशन खत्म करवाया था। उसके बाद 2011 में अन्ना हजारे के अनशन को भी यूपीए सरकार ने खत्म करवाया। अभी सोनम वांगचुक के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सोनिया गांधी के कहने पर ही जंतर–मंतर गए। क्योंकि सोनिया ने याद दिलाया कि 1984 में अपनी मौत से कुछ महीने पहले सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल का अनशन खत्म करवाया था। लेकिन मोदी सरकार का रवैया अनशन खत्म करवाने की जगह अपना जोर दिखाने का है। इसलिए आंदोलन के बीच ही पुलिस कमिश्नर बदल गए और आंदोलनकारियों के हौसले पस्त करने की कोशिश की। मगर यहां बाजी उल्टी पड़ गई, शनिवार को जंतर–मंतर पर सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा लोग पहुंचे, ये सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। जिस तरह के नारे यहां लगे, पोस्टर लहराए गए, उनसे जाहिर हो गया कि अब धर्मेन्द्र प्रधान से ज्यादा नरेन्द्र मोदी के लिए नाराजगी कायम हुई है।दरअसल सत्ता के बारह सालों में नरेन्द्र मोदी ने कई बार जनभावनाओं को कुचलने का काम किया है और ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें लोगों की जान दांव पर लगी। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना लॉकडाउन जैसे फैसले देशहित के नाम पर लिए गए और इनमें लोगों को जानलेवा नुकसान हुआ। वहीं जब अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए लोगों ने शाहीन बाग जैसे आंदोलन किए, जब किसान तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर सड़क पर बैठे रहे, जब महिला पहलवान जंतर–मंतर पर इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बैठीं तो मोदी सरकार ने उनके साथ कैसा सलूक किया, ये भी देश ने देखा। किसान आंदोलन को तो सरकार पूरी तरह कुचलने के लिए सारे हथकंडे अपना ही रही थी, लेकिन राकेश टिकैत की आंखों से जब नाइंसाफी के खिलाफ आंसू टपके तो सारा मामला पलट गया। जिस किसान आंदोलन को मोदी सरकार ने खत्म समझ लिया था, उसमें नयी जान पड़ गई। आखिरकार मोदी को अपने कदम पीछे लेने पड़े। इसके बावजूद मोदी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा और आम जनता की उपेक्षा करना उसने जारी रखा। अब जंतर–मंतर पर अभिजित दिपके के आंसू भी टपके हैं और सोनम वांगचुक की जगह दिपके ने अनशन करना शुरु कर दिया है। देखना होगा, कल का दिन सियासत में कैसा मोड़ लाता है।

एसबीएसपी ने पिछड़े, दलितों के सम्मान, सुरक्षा की मांग की

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय महासचिव डॉ. जेपी सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित और अतिदलित समाज के सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। राष्ट्रीय महासचिव डॉ. जेपी सिंह ने कहा कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा इन वर्गों के विरुद्ध लगातार जातिसूचक, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इससे समाज के वंचित वर्गों में गहरा आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति या समाज को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। ज्ञापन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों को कथित तौर पर धमकाने, प्रताड़ित करने, उनकी भूमि पर अवैध कब्जा करने और जातिसूचक टिप्पणियां करने का उल्लेख किया गया है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर समाज में वैमनस्य फैलाने जैसी घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई है। एसबीएसपी ने मांग की है कि ऐसे प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और राजनीतिक प्रभाव या पद की परवाह किए बिना दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने जातिसूचक एवं भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई और गरीब एवं वंचित वर्गों के उत्पीड़न के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित और अतिदलित समाज के सम्मान, सुरक्षा एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। साथ ही, समाज में जातिवादी मानसिकता के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की गई है।

पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण और सकारात्मक चिंतन की सबसे सशक्त आधारशिला - प्रो. रणजीत पांडेय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। गांधी स्मारक पीजी कॉलेज, समोधपुर में बुधवार को श्पुस्तक पठन एवं पुस्तक समीक्षाश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं ने विभिन्न विषयों की पुस्तकों का अध्ययन कर विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रारूप के अनुसार उनकी समीक्षा प्रस्तुत की। प्राचार्य प्रो. रणजीत कुमार पाण्डेय ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन की आदत विकसित करने का आह्वान किया। महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. रणजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान छात्र–छात्राओं ने अपनी रुचि के अनुरूप विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया और पुस्तक का परिचय, सारांश, प्रमुख विचार, प्राप्त सीख तथा निष्कर्ष के आधार पर समीक्षा तैयार की। प्राचार्य प्रो. रणजीत कुमार पाण्डेय ने कहा, श्पुस्तकें केवल जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण की सशक्त आधारशिला हैं। नियमित अध्ययन से विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। पुस्तक पठन की आदत जीवनभर सीखने की प्रेरणा देती है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।ष कार्यक्रम के दौरान प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए पुस्तक पठन की उपयोगिता, अध्ययन संस्कृति तथा आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक लेखन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों में अध्ययन संस्कृति, बौद्धिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक चिंतन तथा साहित्य के प्रति रुचि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में प्रो. अरविंद कुमार सिंह, प्रो. राकेश कुमार यादव, प्रो. लक्ष्मण सिंह, डॉ. नीलमणि सिंह, डॉ. अवधेश कुमार मिश्रा, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. अविनाश कुमार वर्मा, डॉ. आलोक प्रताप सिंह विसेन, डॉ. वंदना तिवारी, डॉ. विष्णुकांत त्रिपाठी, विकास कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

एग्री रूरल और गंगेग्राम परियोजनाओं से पर्यटन को मिल रही नई पहचान

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एग्री रूरल और गंगेग्राम रूरल टूरिज्म परियोजनाओं के माध्यम से चयनित गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं के अनुरूप पर्यटन विभाग की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति, लोक कला, कृषि आधारित जीवन शैली और गंगा तटीय विरासत को पर्यटन से जोड़ते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित करना है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना के तहत पर्यटन ग्रामों में होम–स्टे, फार्म–स्टे, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा स्थानीय महिलाओं, युवाओं, होम–स्टे संचालकों और अन्य हितधारकों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण पर्यटन को मजबूत आधार मिल रहा है और गांवों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इससे युवा पीढ़ी पर्यटन उद्योग से जुड़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान मिल रही है। वर्ष 2024 में बागपत जिले के पूरा महादेव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2025 में बहराइच जिले के कारीकोट गांव को इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

मलिहाबाद पुलिस ने गैर–जमानती वारंट के आरोपी को किया गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। कमिश्नरेट लखनऊ की मलिहाबाद थाना पुलिस ने गैर–जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के अनुपालन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर–जमानती वारंटों के अनुपालन तथा वांछित एवं वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना मलिहाबाद पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में 21 जुलाई को क्षेत्र भ्रमण, अपराध नियंत्रण, कानून–व्यवस्था ड्यूटी, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग तथा वारंटियों की तलाश के दौरान पुलिस टीम ने ग्राम फिरोजपुर में दबिश देकर एक वारंटी को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान चन्द्रपाल, पुत्र स्वर्गीय महावीर पासी, निवासी ग्राम फिरोजपुर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 107/2007, केस संख्या 1029/2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 447, 506 तथा वन अधिनियम की धारा 4/10 के तहत गैर–जमानती वारंट जारी किया गया था।

मौलवीगंज में संयुक्तउद्योग व्यापार मंडल की नगर इकाई का गठन, 50 से अधिक व्यापारियों ने ली सदस्यता

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के संगठन विस्तार अभियान के अंतर्गत आज मौलवीगंज में नगर इकाई का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री गीता गुप्ता की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया तथा 50 से अधिक व्यापारियों ने संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

बैठक में सर्वसम्मति से श्री मोहम्मद रिजवान खान को नगर अध्यक्ष, श्री गुलाम मोहम्मद को नगर महासचिव, श्री संजीव कुमार राठौर को नगर सचिव तथा श्री इस्लाम खान को नगर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्राची पांडे, राष्ट्रीय प्रभारी श्री विष्णु शंकर तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री करण मोहन त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक पाल, प्रदेश प्रभारी श्री सत्य सिंह, जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता चटर्जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती रुचि सिंह, प्रदेश महामंत्री श्रीमती अनीता तिवारी, श्रीमती रीता नाथ, श्रीमती सरिता बाजपेयी, मीडिया प्रभारी श्री सुभाष चंद्र, श्री सलमान सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री गीता गुप्ता ने कहा कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज व्यापारियों के सामने बढ़ती महंगाई, बाजारों में यातायात एवं पार्किंग की समस्या, अतिक्रमण, छोटे व्यापारियों पर बढ़ता आर्थिक दबाव तथा ऑनलाइन व्यापार से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। इन सभी मुद्दों को संगठन शासन एवं प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाएगा और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेगा। बैठक में सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों के हितों की रक्षा करने, संगठन को प्रत्येक बाजार तक पहुँचाने तथा व्यापारियों की हर समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत एवं शुभकामनाओं के साथ हुआ।

पोस्टर में सानिया मौर्य, काव्य लेखन में हिमांशी अव्वल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार आयोजित दीक्षोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान द्वारा षविकसित भारत /2047ष एवं ष्मेरी माँष विषय पर पोस्टर एवं काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन एस. पी. गुप्ता मेमोरियल लाइब्रेरी में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों के छात्र–छात्राओं ने बढ़–चढ़कर भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं साहित्यिक संवेदनशीलता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों और कविताओं के माध्यम से विकसित भारत के सपनों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका तथा माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति दी। पोस्टर प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. वनिता सिंह, डॉ. प्रियंका कुमारी, डॉ. शुभम सिंह एवं डॉ. आश्रेया दुबे ने किया। प्रतियोगिता में सानिया मौर्य (दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान) ने प्रथम, आशीष शैलेंद्र प्रजापति (बायोटेक्नोलॉजी विभाग) ने द्वितीय तथा खुशी सिंह (एमबीए–एचआरडी) एवं अंकुर मौर्य (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग) ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। काव्य लेखन प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. इंद्रजीत सिंह एवं डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने किया। इसमें हिमांशी श्रीवास्तव (बायोटेक्नोलॉजी विभाग) ने प्रथम, अनुराग यादव (फार्मेसी विभाग) ने द्वितीय तथा शशिकांत (दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनुराग मिश्र ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ष्इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन, साहित्यिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती हैं।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- छात्रों की मांग जायज, राहुल-अखिलेश का आंदोलन राजनीति

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी सरकार के पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दिल्ली में नीट अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को जायज बताया लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आंदोलन को राजनीतिक करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि छात्रों की मांग उचित है और पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए थे लेकिन प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता छात्रों को उकसाने पहुंचे जबकि लाठीचार्ज के समय उन्हें छोड़कर चले गए।ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में खुलेआम नकल और पेपर लीक होते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि अब नकलविहीन परीक्षाएं हो रही हैं और पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से खुरपका–मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीकाकरण टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा पौधरोपण और जल संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज का वह समर्थन नहीं करते लेकिन जो लोग छात्रों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में नौकरियों के लिए बोली लगती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने बिना भ्रष्टाचार के प्रदेश में नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है, जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं।

क्वीन मेरी की आईसीयू में एसी खराब होने पर रिपोर्ट तलब

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीन मेरी) की आईसीयू में एसी खराब होने के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। केजीएमयू प्रशासन से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भी मांगी है। एसी खराब होने से मरीजों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। गंभीर प्रसूताओं में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया था। वेंटिलेटर जैसे जीवनरक्षक उपकरणों के संचालन पर भी असर पड़ने की आशंका थी।

लारी में अब 24 घंटे खुलेगा एचआरएफ स्टोर

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू की लारी ओपीडी परिसर स्थित हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) का स्टोर अब 24 घंटे सातों दिन खुलेगा। काउंटर पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी रहेगी। इससे ओपीडी में आने वाले व भर्ती मरीजों को राहत मिलेगी। अभी तक रात में स्टोर बंद होने से तीमारदारों को दवा बाहर से महंगी दर पर लेनी पड़ती थी। मंगलवार को कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने स्टोर का शुभारंभ किया। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि लारी ओपीडी में खुला एचआरएफ स्टोर पहले हर दिन 150–200 मरीजों को सेवाएं देता था, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 800–1,000 मरीजों तक कर दी गई है। कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य मरीजों को बेहतर, सुलभ और मरीज केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। एचआरएफ के अध्यक्ष प्रो. कुमार शांतनु ने कहा कि लारी में बढ़ते मरीज भार को देखते हुए इस स्टोर का विस्तार बेहद जरूरी था। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. ऋषि सेठी ने कहा कि ओपीडी में आने वाले अधिकांश मरीज गंभीर हृदय रोगों से पीड़ित होते हैं,।

जिला अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था में गंभीर लापरवाही डीएम नाराज अस्पताल में सफाई कार्य देख रही संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जन आरोग्य केंद्र, टीकाकरण व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट, जन सुविधा केंद्र सहित चिकित्सालय की समग्र व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया तथा कमियों सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। जन आरोग्य केंद के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान कार्यालय सुव्यवस्थित नहीं पाया गया तथा परिसर में विभिन्न स्थानों पर पान की पीक एवं गंदगी मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा कार्यालयों को व्यवस्थित रखा जाए। टीकाकरण व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने टीकाकरण की प्रगति एवं अभिलेखों की जानकारी प्राप्त की तथा नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील अवस्था में नहीं पाया गया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल उसे संचालित कराने एवं आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एमसीएच वार्ड के निरीक्षण में बेडशीट गंदी पाई गई तथा वार्ड में लगा विद्युत बोर्ड खुला हुआ मिला, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने वार्ड में भर्ती मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से पूछा कि उन्हें भोजन में क्या–क्या उपलब्ध कराया गया तथा भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों को निधारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान फायर अलार्म प्रणाली सही स्थिति में नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त मरीजों का पंजीकरण (पेशेंट रजिस्टर) भी व्यवस्थित नहीं मिला। जिलाधिकारी ने इन कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए तथा कहा कि अस्पताल में सुरक्षा एवं अभिलेखों का उचित रख–रखाव अत्यंत आवश्यक है। अस्पताल के शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मरीजों के उपयोग में आने वाला स्ट्रेचर भी गंदा पाया गया, जिसे तत्काल साफ कराने एवं भविष्य में स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अस्पताल में सफाई कार्य देख रही संस्था को तत्काल कारण बताओ (शो कॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में गंदगी, अव्यवस्था एवं लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कमियों को समयबद्ध ढंग से दूर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण में पाई गई सभी कमियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

दीक्षोत्सव में खेल प्रतिभाओं का दमदार प्रदर्शन विजेता खिलाड़ियों को कुलपति ने किया सम्मानित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांतपूर्व दीक्षोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को परंपरागत खेल प्रतियोगिताओं का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। रस्साकशी एवं कबड्डी प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं विभागों के छात्र–छात्राओं ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। महिला रस्साकशी प्रतियोगिता में एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) की टीम उपविजेता रही, जबकि बी.एससी. जेडबीसी की टीम ने तृतीय स्थान हासिल किया। पुरुष रस्साकशी प्रतियोगिता में बीसीए की टीम विजेता बनी। एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी की टीम द्वितीय तथा बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) की टीम तृतीय स्थान पर रही। महिला कबड्डी प्रतियोगिता में बी.एससी. जेडबीसी की टीम ने प्रथम, एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी की टीम ने द्वितीय तथा बी.एससी. बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में बीसीए की टीम विजेता घोषित हुई। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी छात्र–छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का सशक्त माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का भी विकास करते हैं। अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. प्रदीप कुमार के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण समारोह में खेल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, रजनीश, राजेश, शिक्षक डॉ. संजीव मौर्य, डॉ. ईशानी भारती, डॉ. ऋषि श्रीवास्तव, डॉ. विवेक सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित रहे।

प्रदेश में बनेंगे दो नए एक्सप्रेसवे, विंध्य और विंध्य–पूर्वांचल स्पर लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में दो नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इनमें विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य–पूर्वांचल स्पर लिंक एक्सप्रेस वे शामिल हैं। इसके अलावा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब एक किलोमीटर बढ़ाई गई है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया। इससे संबंधित प्रस्तावों को मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे लिंक एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। क्योंकि लखनऊ–कानपुर मार्ग और लखनऊ–रायबरेली के पास प्रस्तावित इंटरचेंज की वजह से बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए एक्सप्रेस वे की प्रस्तावित लंबाई 49.80 किलोमीटर की जगह 50.98 किलीमीटर की गई है। बढ़ी हुई एक किलोमीटर से ज्यादा लंबाई से किसी तरह का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और न ही कोई नया बजट पास होगा। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से वाया फरुर्खाबाद लिंक एक्सप्रेस का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। इसका अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया। जल्द दो लिंक परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन की निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। चयनित एजेंसी को लगभग तीन साल में निर्माण कार्य पूरा करना होगा और इसके बाद पांच वर्षों तक अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के छह लेन ग्रीनफील्ड मार्ग को भी मंजूरी दी। इस परियोजना पर लगभग 26315 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।विंध्य–पूर्वांचल स्पर लिंक (विकल्प–1) को भी स्वीकृति मिल गई है। लगभग 9039 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को आपस में जोड़ेगी।

बदहाल में मिली सफाई, निजी कंपनी पर तीन लाख का जुर्माना

लखनऊ, (संवाददाता)। सफाई में लापरवाही पर नगर निगम ने निजी कंपनी लॉयन एनवायरो पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रायबरेली रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी के कई सेक्टरों में निरीक्षण के दौरान मिली गंदगी और कूड़ा उठान में लापरवाही पर की गई है। नगर निगम ने शहर के 110 वार्ड में से 33 में सफाई का काम निजी कंपनी लॉयन एनवायरो को दिया है। जिस पर हर महीने आठ से दस करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी संस्था सफाई कार्य में लापरवाही कर रही है। मंगलवार को अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद राव ने वृंदावन कॉलोनी के सेक्टर छह, आठ व आकाश एन्क्लेव इलाके का निरीक्षण किया। सेक्टर–8 स्थित पड़ावघर के आसपास भारी मात्रा में कूड़ा और लंबे समय से अनिस्तारित ग्रीन वेस्ट मिला। दोनों पोर्टेबल कॉम्पेक्टर भी खराब थे। एजेंसी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, सेक्टर–6 स्थित पड़ावघर पर अस्पताल अपशिष्ट और अन्य कूड़ा फैला हुआ था। पूर्व निरीक्षण के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ था।

जमीनी विवाद में 62 वर्षीय अधेड की पीट–पीटकर की हत्या

अयोध्या।जिले के थाना क्षेत्र हैदरगंज के कुआडाड गांव में जमीनी विवाद में एक अधेड की हमलावरों ने पीट–पीटकर हत्या कर दी।हमलावर मृतक के घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों को लाठी–डंडे और धारदार हथियारों से लहूलुहान कर दिया।मिली जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की है।हैदरगंज थाना क्षेत्र के कुआडाड निवासी मृतक के पुत्र बालोद ने तहरीर में बताया कि गांव के ही पड़ोसी राजकुमार और राम अनुज पुत्र राम जन्म के बीच मारपीट हो गई थी।बीच–बचाव कराने के लिए उनके पिता चौतू राम पुत्र भभूती उम्र 62 वर्ष और खुशीराम पुत्र राजकुमार मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पहले से लाठी–डंडा, कुल्हाड़ी व अन्य धारदार हथियारों से लैस मानिक राम पुत्र राम जन्म, हरेंद्र व उनके साथियों ने चौतू राम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने चौतू राम को लाठी–डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया और राजकुमार को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हल्ला–गुहार मचने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। इस हमले में नीरज, गुंजन, राजेश्वरी सहित कई लोग घायल हुए हैं।सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।जबकि थोड़ी देर बाद एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ बीकापुर सुनील कुमार सिंह, कोतवाल देवेंद्र पांडे और तारुन एसओ लालचंद सरोज भी पहुंचे।परिजनों के विरोध के कारण करीब 5 घंटे बाद घायलों को मेडिकल और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध मे एसपी ग्रामीण ने बताया कि तहरीर के आधार पर राम अनुज, मानिक राम, बाबूराम, हरेंद्र सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध दर्ज किया गया है।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।गांव में शांति व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात है।

घर में इनवर्टर के पास काम करते समय करंट के चपेट में आकर महिला की हुई मौत

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को एक 32 वर्षीय महिला की घर में इनवर्टर के पास काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।मिली जानकारी के अनुसार, कुमारगंज थाना क्षेत्र के हरदोईया पड़ाईन गांव निवासी प्रियंका 32, पत्नी अनिल कुमार, सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर में इनवर्टर के पास कुछ काम कर रही थीं। इसी दौरान वह अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गईं।घटना के तुरंत बाद, परिजन उन्हें उपचार के लिए सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज लेकर पहुंचे। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना की सूचना कुमारगंज थाना पुलिस को दी।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच–पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतका अपने पीछे पति अनिल कुमार और दो छोटे.बच्चों को छोड़ गई हैं।उनका बड़ा बेटा तीन वर्ष का है, जबकि बेटी की उम्र डेढ़ वर्ष है। घटना की जानकारी होने के बाद ग्राम प्रधान अमर कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए हैं।

आशीष कुमार राय बने मिल्कीपुर लेखपाल संघ के अध्यक्ष,48 मत पड़े,एक मत हुआ निरस्त

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा मिल्कीपुर की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए मंगलवार को तहसील सभागार में चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर वेद प्रकाश वर्मा और आशीष कुमार राय प्रत्याशी रहे। जबकि अन्य सभी पदों पर एक–एक प्रत्याशी होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन जिला मंत्री नंदलाल वर्मा ने किया। अध्यक्ष पद के लिए अपराह्न तीन बजे मतदान शुरू हुआ। कुल 57 मतदाताओं में से 48 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की प्रक्रिया शाम 4.39 बजे समाप्त हुई,जिसके बाद 4.41 बजे मतगणना शुरू कराई गई। मतगणना के दौरान एक मत निरस्त पाया गया। मतगणना के बाद आशीष कुमार राय को अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया गया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सर्वेश नाथ गुप्ता,कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रेम प्रकाश पाठक,मंत्री पद पर ज्ञानेंद्र देव मिश्रा,उपमंत्री पद पर नेहा त्रिपाठी,कोषाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार आदित्य,ऑडिटर पद पर क्षमा मिश्रा तथा मीडिया प्रभारी पद पर दिनेश कुमार पांडे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी लेखपालों के हितों की रक्षा करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाएगी। शपथ ग्रहण के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई। इस मौके पर सभी लेखपाल कर्मचारी मौजूद रहे

सावन के पहले सोमवार पर गहनाग बाबा व आस्तीक बाबा मेले की सुरक्षा को लेकर एसडीएम,सीओ ने किया स्थलीय निरीक्षण

(डॉक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। सावन माह के पहले सोमवार से शुरू होने वाले प्रसिद्ध गहनाग बाबा एवं पौराणिक आस्तीक बाबा मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए मिल्कीपुर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को उप जिलाधिकारी पवन कुमार शर्मा,सीओ मिल्कीपुर पीयूष तथा थाना प्रभारी निरीक्षक इनायतनगर राजेश सिंह ने पुलिस बल के साथ दोनों मेला स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अयोध्या–रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित गहनाग बाबा देवस्थान तथा थाना इनायतनगर से लगभग पांच किलोमीटर दूर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के समीप स्थित हजारों वर्ष पुराने पौराणिक मंदिर आस्तीक बाबा देवस्थान का भ्रमण किया। सावन के पहले सोमवार को दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई।उप जिलाधिकारी पवन कुमार शर्मा व सीओ मिल्कीपुर पीयूष ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मेले में महिला उपनिरीक्षक, महिला पुलिसकर्मियों के साथ थाना इनायतनगर पुलिस, अतिरिक्त पुलिस बल तथा पीएसी की तैनाती की जाएगी।संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में पूजा–अर्चना कर सकें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे यातायात एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।अधिकारियों ने विश्वास जताया कि प्रशासन और जनता के सहयोग से सावन का मेला शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा।

‘जिलाधिकारी ने राजकीय जिला पुस्तकालय का किया आकस्मिक निरीक्षण’

’रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’ ’हरदोई’ गुरुवार को जिलाधिकारी अनुनय झा ने राजकीय जिला पुस्तकालय का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं

देखी। जिलाधिकारी ने पुस्तकालय परिसर, अध्ययन कक्षों, कार्यालय कक्ष आदि का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जागरुकता अभियान शुरु

गोरखपुर, (संवाददाता)। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत मंगलवार को गोद लिए गांव रामलखना में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। 11वें दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय महिला कर्मचारियों, छात्राओं और रामलखना गांव की पात्र महिलाओं

व किशोरियों का एचपीवी टीकाकरण कराएगा। इसे देखते हुए महिला कल्याण एवं उत्पीड़न विरोधी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. मीनू, सदस्य सचिव डॉ. प्रियंका राय, डॉ. ज्योति, डॉ. रीना बंका और डॉ. भारती शुक्ला ने ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को एचपीवी संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर के खतरे और टीकाकरण के लाभों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 50 महिलाओं और किशोरियों ने हिस्सा लिया। कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे गंभीर कैंसर में शामिल है। एचपीवी टीका इसके प्रभावी बचाव का सुरक्षित माध्यम है। जागरूकता और समय पर टीकाकरण से हजारों महिलाओं का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है।

बिना बैनामा किसान की जमीन पर जेसीबी से खुदाई, ग्रामीणों ने रुकवाया काम

अयोध्या। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में बिना सहमति और बिना बैनामा कराए किसान की जमीन पर निर्माण शुरू करने को लेकर गुरुवार को विवाद हो गया। पीडब्ल्यूडी की कार्यदाई संस्था छात्र शक्ति के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने मौके पर रोक दिया।सूचना पर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता भी पहुंचे और काम फिलहाल रोक दिया गया। घटना कुढाकेशवपुर उपहार स्थित गाटा संख्या 643 निकट काली चौराहा की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में भी पीडब्ल्यूडी ने बिना अनुमति के इसी भूमि पर गिट्टी डालकर सड़क बनाई थी और जेसीबी से नाले के लिए गड्ढा खोद दिया था। क्या हुआ गुरुवार सुबह करीब 10 बजे छात्र शक्ति के लेबर और जेसीबी हाईवे किनारे मिट्टी पटाई कर सड़क समतल करने पहुंचे। सूचना मिलते ही भू–स्वामी गोस्वामी, संदीप चंद्र पांडे, प्रेमचंद पांडे सहित अन्य किसान मौके पर पहुंचे। उन्होंने अवैध निर्माण का विरोध करते हुए मशीनें रुकवा दीं और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर कार्य बंद कर दिया गया। करीब एक घंटे बाद पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता विपिन कुशवाहा अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंचे। किसानों का बयान किसानों ने कहा कि जमीन उनकी निजी है। अब तक न पीडब्ल्यूडी ने बैनामा किया है और न राजस्व विभाग से सहमति ली गई है। मुआवजा दिए बिना निर्माण गलत है। उन्होंने नियमानुसार अधिग्रहण के बाद ही काम शुरू करने की मांग की। अधिकारी का पक्ष का बयान । विपिन कुशवाहा ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण शासन की प्राथमिकता है। राजस्व टीम के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण व मुआवजे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तब तक विवादित स्थल पर काम बंद रहेगा।

‘मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित एक परिवार ने मुख्यमंत्री का ह्रदय से जताया आभार’

’ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’ ’शाहजहांपुर’ विकास खंड पुवायां के अंतर्गत ग्राम पंचायत जटियापुर बुजुर्ग निवासी लीलावती पत्नी स्व0 केशव

लाल कभी कच्चे एवं जर्जर मकान में रहने को विवश थीं। बरसात के मौसम में घर की छत टपकती थी और परिवार को हमेशा असुरक्षा एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़

मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

अयोध्या।मामूली विवाद में खून का प्यासा छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।आनंद फानन में लोगों ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले आए जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रायगंज चौकी में गुरुवार को खाले के पूरवा मे किसी बात को लेकर बड़े भाई आदर्श सिंह तथा छोटे भाई अभिषेक सिंह के बीच कहां सुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई अभिषेक सिंह ने बड़े भाई आदर्श सिंह पर चाकू से हमला कर दिया जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बड़े भाई आदर्श सिंह को गंभीर अवस्था में लोगों ने अस्पताल ले जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह ने बताया कि आरोपी छोटे भाई अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया।

व्यापार बंधु की बैठक में उठेगा पार्किंग, जलभराव ,चटोरी गली का मुद्दा

गोरखपुर, (संवाददाता)। कलेक्ट्रेट सभागार में 23 जुलाई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली व्यापार बंधु की मासिक बैठक इस बार हंगामेदार रहने के आसार हैं। शहर के व्यापारी पार्किंग संकट, बारिश के दौरान हुए जलभराव, चटोरी गली का रास्ता खुलवाने और राप्ती कॉम्प्लेक्स में हुए भारी नुकसान समेत कई मुद्दों पर प्रशासन को घेरने की तैयारी में हैं। व्यापारियों से बैठक से पहले अपनी समस्याएं लिखित रूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि संबंधित विभागों से कार्रवाई रिपोर्ट ली जा सके। हाल की मूसलाधार बारिश में असुरन–गीता वाटिका मार्ग स्थित राप्ती कॉम्प्लेक्स के बगल में नाले की दीवार टूटने से परिसर और दुकानों में पानी भर गया था। इससे व्यापारियों का करोड़ों रुपये का माल खराब हो गया। व्यापारी मणिनाथ गुप्ता ने कहा कि बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए प्रभावित व्यापारियों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी। समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने कहा कि पिछली व्यापार बंधु बैठक में भी चटोरी गली का रास्ता खोलने का मुद्दा उठाया गया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चटोरी गली के दुकानदार नवीन सिंह का कहना है कि रास्ता खुलने से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी। व्यापारी पवन जालान ने कहा कि नगर निगम हर वर्ष जलभराव रोकने के दावे करता है और करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। तीन दिन की बारिश ने सभी दावों की पोल खोल दी। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया खाद्य सुरक्षा विभाग कीअनावश्यक कार्रवाईयों के मुद्दे को उठाएंगे।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद अयोध्या द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन 26 जुलाई को

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद अयोध्या द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन 26 जुलाई दिन रविवार को 10 बजे से अयोध्या की धरती पर फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव सभागार में होगा जिसमें पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी शिरकत करेंगे। उक्त बात की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष देव बक्श वर्मा ने बताया कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी अयोध्या की पावन धरती पर पत्रकार सम्मेलन 26 जुलाई दिन रविवार को 10.00 बजे से होगा जिसमें स्मारिका ग्राम्य गौरव का विमोचन होगा।पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों और विभिन्न मंडलों तथा प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी गण भाग लेंगे।मुख्य अतिथि रणंजय कुमार वर्मा जिला जज अयोध्या व एल. वेंकटेश्वर लू,पूर्व अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन,होंगे विशिष्ट अतिथि .राजेंद्र सिंह राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश,व सोमेन बर्मा उप पुलिस महा निरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या होंगे।मुख्य वक्ता देवी प्रसाद गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, अध्यक्षता महेंद्र नाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश करेंगे।

अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल

अयोध्या। रायबरेली हाईवे पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।यह घटना इनायतनगर थाना क्षेत्र के मुंगीशपुर गांव के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि किशोर बाइक समेत हाईवे किनारे गड्ढे में जा गिरा,जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और 1033 एंबुलेंस को सूचना श्दी। सूचना मिलने पर एंबुलेंस कर्मी और इनायतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम में सीसी प्रभारी जोखन यादव और कांस्टेबल अशोक वर्मा शामिल थे। घायल किशोर को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मिल्कीपुर ले जाया गया।सीएचसी में चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।पुलिस के अनुसार, घायल की पहचान इनायतनगर थाना क्षेत्र के मंजनाई पूरे पिड़िया गांव निवासी अंकित (18) पुत्र राम गरीब के रूप में हुई है। बताया गया कि अंकित शनिवार सुबह मिल्कीपुर से कुचेरा जा रहा था, तभी मुंगीशपुर गांव के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर इनायतनगर थाने पहुंचा दिया है। अज्ञात वाहन की पहचान और उसके चालक की तलाश की जा रही है। घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा–तफरी का माहौल रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कर नियंत्रित किया।

वनस्पति विज्ञान विभाग की कमान अब प्रो. रामवंत संभालेंगे

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की कमान अब अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पादप वैज्ञानिक प्रो. रामवंत गुप्ता के हाथों में होगी। उन्होंने मंगलवार को प्रो. अनिल द्विवेदी से विभागाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। प्रो. गुप्ता पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, जलवायु–अनुकूल कृषि और फसल सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य कर चुके हैं। उन्होंने देश–विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया है और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों के साथ शोध सहयोग स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में वह विश्वविद्यालय में निदेशक, अंतरराष्ट्रीय कार्य, कंसल्टेंसी सेल के समन्वयक, कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान (आईएएनएस) के समन्वयक तथा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अनुपालन अधिकारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद प्रो. गुप्ता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक प्रयोगशालाओं का विकास, अंतःविषयक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना होगी। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने विश्वास जताया कि उनकी शैक्षणिक विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव से वनस्पति विज्ञान विभाग नई उपलब्धियां हासिल करेगा

दोस्तों ने की थी प्रेमसागर की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र में प्रेमसागर यादव (30) की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया। जांच में सामने आया कि तीन माह पहले शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद और थप्पड़ मारने की घटना का बदला लेने के लिए दो दोस्तों ने सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों की पहचान संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के रावतपुर निवासी अखिलेश यादव (20), अजीत कुमार यादव उर्फ सिंटू (40) और मामतपुर कठर निवासी सुधीर यादव (21) के रूप में हुई। इनमें अखिलेश और अजीत, प्रेमसागर के करीबी दोस्त थे। साजिश के तहत पहले प्रेमसागर को शराब पिलाकर नशे में किया गया फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर रॉड और डंडे से हमला किया गया। आरोपियों ने प्रेमसासगर को मृत समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 19 जुलाई की सुबह बैजलपुर ग्राम पंचायत भवन के पास सड़क किनारे प्रेमसागर अचेत अवस्था में मिले थे। परिजन उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां सोमवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रेमसागर के पिता ज्ञानेंद्र यादव की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि करीब तीन माह पहले शराब पार्टी के दौरान प्रेमसागर और उसके दोस्त अखिलेश व अजीत के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद के दौरान प्रेमसागर ने अजीत उर्फ सिंटू को थप्पड़ मार दिया था। इसी घटना के बाद दोनों ने मन में रंजिश पाल ली और बदला लेने के लिए प्रेमसागर की हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक, 18 जुलाई की शाम अखिलेश, प्रेमसागर को बहाने से गिठनी चौराहे पर ले गया और उसे खूब शराब पिलाई। नशे में बेसुध होने पर उसने अजीत को फोन कर बुलाया। अजीत अपने साथी सुधीर के साथ सफेद रंग की कार लेकर मौके पर पहुंचा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।